



125 दिन की रोजगार गारंटी



Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) : VB - G RAM G

(विकसित भारत - जी राम जी) Act, 2025

अब गांव के लोग खुद बनाएंगे विकसित ग्राम पंचायत योजना



विकसित ग्राम पंचायत से विकसित भारत की ओर

कांग्रेस में सभी संगठनात्मक परिवर्तन केरल चुनाव के बाद में ही होंगे

इसका प्रमुख कारण है, के.सी. वेणुगोपाल, वे केरल में मु.मंत्री बनने को लालायित हैं, अभी राहुल के निकटतम व्यक्ति होने के कारण, वेणुगोपाल ही, परीक्ष रूप से कांग्रेस चला रहे हैं

नितिन नबीन निर्विरोध भाजपा अध्यक्ष निर्वाचित

—जाल खंभाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 19 जनवरी। भाजपा के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए सोमवार को केवल बिहार के 45 वर्षीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के ही नामांकन पत्र दाखिल किए गए। निर्वाचन अधिकारी डॉ. के. लक्ष्मण ने घोषणा की कि चूंकि शीर्ष पार्टी नेताओं ने केवल नितिन नबीन का ही नामांकन दाखिल किया है, इसलिए वे निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जाते हैं।

नितिन नबीन के भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने की औपचारिक घोषणा मंगलवार को

■ औपचारिक घोषणा भाजपा मुख्यालय में मंगलवार 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में होगी।

सुबह 11.30 बजे पार्टी मुख्यालय में की जाएगी। निर्वाचन अधिकारी के. लक्ष्मण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में इसकी घोषणा करेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी स्वयं नितिन नबीन के पार्टी अध्यक्ष चुने जाने के समारोह में उपस्थित रहना चाहते थे।

निवर्तमान भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तथा वरिष्ठ नेताओं (शेख अंतिम पृष्ठ पर)

मणिकर्णिका घाट के डोम राजा की अर्जी भारी पड़ेगी भाजपा को?

डोम राजा विश्वनाथ चौधरी ने प्र.मंत्री पर दबाव डाला था कि इस घाट का भी काशी विश्वनाथ कोरिडोर की भांति आधुनिकीकरण करवा दें

—श्रीनंद झा—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 19 जनवरी। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास योजना को शुरुआत में एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है, जिसका असर अगले वर्ष होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा की संभावनाओं पर प्रतिकूल रूप से पड़ सकता है।

इस परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2023 में किया था, लेकिन इसका विलपोषण (फंडिंग) काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है और इसे "रूप फाउंडेशन" नामक संस्था द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

मणिकर्णिका तीर्थ कोरिडोर विकास परियोजना के तहत, बुलडोजर चलाए जाने और ऊँची "मढ़ी" (ऊंचे चबूतरे) से मूर्तियों को हटाकर गिराए जाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वयरल हो गईं। इसके बाद इतिहासकारों, अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट और पाल समुदाय जैसे धार्मिक

■ आधुनिकीकरण का प्लान पहले 3000 वर्ग मीटर तक सीमित था, फिर बढ़ाकर 39,350 वर्ग फ्लेटफॉर्म बनाना तय किया गया

■ यह आधुनिकीकरण का प्लान चार चरणों में पूरा होना है और फ्लेटफॉर्म बनने के बाद, एक साथ 19 दाह संस्कार किए जा सकेंगे, तथा इसके लिए कई तरह की सार्वजनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

■ पर, प्रोजेक्ट की प्रथम दिन से ही आलोचना शुरू हो गई, इतिहासकार, धार्मिक ग्रुप जैसे अहिल्या बाई होलकर ट्रस्ट, पाल समाज तथा कांग्रेस व समाजवादी पार्टियों द्वारा।

■ इतिहासकार, मुदुला मुखर्जी के अनुसार, जनता में यह भय फैला है कि धार्मिक पवित्र स्थलों का व्यवसायिकीकरण हो रहा है तथा यह भी प्रचारित हो रहा है कि मणिकर्णिका घाट से सटे हुए ही व्यवसायिक मॉल व अन्य बड़े-बड़े कॉमर्शियल स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे।

संगठनों, तथा कांग्रेस और समाजवादी पुनर्विकास के नाम पर आगे किसी भी पार्टी समेत, विपक्षी दलों की ओर से इसकी तीखी आलोचना की गई। (शेख अंतिम पृष्ठ पर)

—रेणु मिश्र—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 19 जनवरी। राहुल गांधी इस समय केरल और के.सी. वेणुगोपाल के बीच फंसे हुए हैं। राहुल गांधी के लिए केरल जीतना इस वक्त की उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जीत के बाद ही यह फैसला लिया जाएगा कि के.सी. वेणुगोपाल को केरल का मुख्यमंत्री बनाया जाए या नहीं। इसी फैसले पर पार्टी के भीतर कई अन्य निर्णय भी निर्भर करते हैं, जैसे के.सी. जाएंगे या नहीं रहेंगे। सूत्रों का कहना है कि केरल चुनावों तक के लिए पार्टी के सभी संगठनात्मक फैसलों को टाल दिया गया है। एक वरिष्ठ नेता, जो शीर्ष स्तर की गतिविधियों से वाकिफ हैं, ने कहा कि राहुल गांधी का

- वेणुगोपाल के रूतबे का यह हाल है कि कांग्रेसअध्यक्ष खड्गो भी उनके सामने मुँह नहीं खोलते और वो ही काम करते हैं, जो वेणुगोपाल इशारा करते हैं।
- अतः वेणुगोपाल अगर केरल जाते हैं तो कांग्रेस में एकदम नए सिरे से समीकरण बनेंगे।
- यहाँ तक कि पहले यह माना जा रहा था कि 14 जनवरी के बाद, राहुल गांधी पार्टी में भारी-भरकम तब्दीलियाँ करेंगे। पर, स्वयं राहुल ने भी अब यह निर्णय टाल दिया है और केरल के विधानसभा चुनावों को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बना लिया है।
- पहले तो वेणुगोपाल चुनाव के पहले ही केरल जाना चाहते थे, पर, उन्हें समझाया गया कि अगर वे चुनाव पहले गए तो सभी दिग्गज उनको हराने में जुट जाएंगे। इस तर्क को स्वीकार करते हुए, वेणुगोपाल ने चुनाव के बाद केरल जाना ही श्रेयस्कर माना।
- अतः, जब तक केरल के चुनाव नहीं होते, वेणुगोपाल का केरल मु.मंत्री पद पर जाना या ना जाना स्थगित है और इसीलिए कांग्रेस में संगठन परिवर्तन की फाइल ठंडे बस्तों में है।

पूरा ध्यान सिर्फ केरल जीतने पर है। वेणुगोपाल चुनाव से पहले ही केरल यह भी पता चला है कि के.सी. भेजे जाने को लेकर काफी उत्सुक थे, लेकिन कुछ शुभचिंतकों ने उन्हें इंतजार (शेख अंतिम पृष्ठ पर)

'ग्रीनलैंड के बारे में उनकी सोच की वजह से उन्हें नोबल प्राइज़ नहीं दिया गया'

एक बच्चे की तरह मचलते हुए, ट्रंप ने "दोषी" यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाया

—अंजन रॉय—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 19 जनवरी। एक चालाक "टीन एजर" (किशोर) की तरह, डॉनल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि नोबेल समिति ने उन्हें शांति पुरस्कार इसलिए नहीं दिया, क्योंकि वे ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने के पक्षधर हैं। किसी और को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने से असंतुष्ट राष्ट्रपति ट्रंप अब यह मान चुके हैं कि यह सम्मान उनसे पूरी तरह दूर है और इसका कारण वे ग्रीनलैंड को वहाँ की जनता और डेनमार्क से, किसी भी तरीके से, हासिल करने के अपने रुख को बता रहे हैं। इसी बीच, अपनी इस कोशिश के खिलाफ बढ़ते विरोध को देखते हुए ट्रंप ने बुइलाहट में उन यूरोपीय देशों पर अतिरिक्त शुल्क (टैरिफ) लगाने की

- यूरोपीय देशों ने जवाबी कार्यवाही करते हुए, अमेरिका द्वारा यूरोप निर्यात सामान पर 108 बिलियन डॉलर का टैरिफ लगाया।
- फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों इस कार्यवाही में अगुवा बने हुए हैं, तथा अमेरिका से सदा "विशेष रिश्ते" की दुहाई देने वाले देश इंग्लैंड ने भी मैक्रों को पूरा समर्थन देने का निर्णय लिया।
- पहला असर तो यह हुआ कि हर बार की तरह, इस संकट व अनिश्चय की स्थिति में डॉलर की तुलना में सोना महंगा हुआ।

घोषणा कर दी, जिन्होंने उनके इस कदम का विरोध किया था। इसका यूरोप में व्यापक रूप से विरोध किया गया है। अब यूरोप अमेरिका से आयात होने वाले 108 अरब डॉलर के अमेरिकी सामान पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की धमकी दे रहा है। यूरोप के कई नेताओं ने अलग-अलग तौर पर उन देशों पर नए टैरिफ लगाने की ट्रंप की (शेख अंतिम पृष्ठ पर)

एसआई पेपर लीक आरोपी जगदीश विश्वाजी को जमानत मिली

जयपुर, 19 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में आरोपी जगदीश विश्वाजी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली की एकलपीठ ने यह आदेश जगदीश विश्वाजी की द्वितीय जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिया। अदालत ने

■ हाई कोर्ट ने कहा कि मामले में अधिकतम तीन वर्ष की सजा का प्रावधान है और आरोपी 22 माह से जेल में है।

अपने आदेश में कहा कि मामले में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन का प्रयोग अधिनियम और आईटी एक्ट के तहत, अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है और याचिकाकर्ता 22 माह से जेल में बंद है। वहीं मुख्य आरोपी राजेश खंडेलवाल को पूर्व में जमानत मिल चुकी है। इसके अलावा, प्रकरण (शेख अंतिम पृष्ठ पर)

'शिव सेना ने मुम्बई को 23 मराठी मेयर दिए हैं, क्या यह परम्परा कायम रहेगी'

शिव सेना (यूबीटी) ने सामना के जरिए शिंदे को मुम्बई में शिव सेना का मेयर बनवाने की चुनौती दी

—जाल खंभाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 19 जनवरी। बीएमसी (बृहन्मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन) चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के बाद मुंबई में एक बार फिर "रिजॉर्ड राजनीति" लौट आई है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) ने कहा है कि नगर निगम चुनाव तो खत्म हो गए हैं, लेकिन असली राजनीति अभी बाकी है। बीएमसी चुनावों में भाजपा ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जबकि ठाकरे परिवार को अपने गड में झटका लगा है। लेकिन अब सबकी नजरें शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिकी हैं।

2022 में शिवसेना में बगावत कर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अखाड़ी सरकार गिराने वाले एकनाथ शिंदे अब भाजपा के सहयोगी हैं और इस नगर निगम चुनाव में उनकी

■ एकनाथ शिंदे भारी दबाव में हैं, इसलिए नतीजे घोषित होते ही उन्होंने अपनी पार्टी के पार्षदों को फाइव स्टार होटल में शिफ्ट कर दिया है।

■ शिंदे आशंकित हैं कि भाजपा उनके पार्षदों को तोड़ सकती है, जो एक बार दलबदल कर सकते हैं, वो दोबारा भी कर सकते हैं।

■ बीएमसी चुनावों में भाजपा ने शानदार 89 सीटें जीती हैं, पर, बहुमत के लिए उसे शिंदे का साथ अवश्य चाहिए, इसलिए शिंदे भाजपा पर दबाव डाल रहे हैं।

पार्टी ने 29 सीटें जीती हैं। नतीजों के बाद जयशंकर और राजनीतिक बयानबाजी के बीच, शिंदे गेट ने अपने पार्षदों को मुंबई के एक पांच सितारा होटल में शिफ्ट करना शुरू कर दिया, जिससे शहर के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को दौर शुरू हो गया। जब चुनावी नतीजे राजनीतिक

पुनर्संयोजन की संभावनाएं पैदा करते हैं, तब "रिजॉर्ड राजनीति" सामने आती है। शिंदे टीम के इस कदम को समझने के लिए बीएमसी के आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है। कुल 227 वार्ड वाली बीएमसी में बहुमत का आंकड़ा 114 है। भाजपा ने 89 सीटें जीती हैं और शिवसेना (शिंदे गेट) को 29 सीटें

मिली हैं। दोनों मिलकर 118 सीटों पर काबिज हैं, जो बहुमत से ज्यादा है। उपमुख्यमंत्री अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसने अकेले चुनाव लड़ा था, ने तीन वार्ड जीते हैं और वह भी अपने सहयोगियों का समर्थन कर सकती है।

दूसरी ओर, शिवसेना (यूबीटी), महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और एनसीपी (शरद पवार) को क्रमशः 65, छह और एक वार्ड मिले हैं। यह संख्या कुल मिलाकर 72 होती है। कांग्रेस ने 24, एआईएमआईएम ने आठ और समाजवादी पार्टी ने दो वार्ड जीते हैं। यदि विपक्ष एकजुट हो जाए तो कुल संख्या 106 हो जाएगी, जो बहुमत से आठ कम है। हालांकि, इन दलों की राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए यह संभावना कम है, फिर भी इसे पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। (शेख अंतिम पृष्ठ पर)

भारत का ट्रंप के गाज़ा पुनर्निर्माण बोर्ड की सदस्यता के बारे में अनिर्णय किसी अनिश्चय व टालम-टोल नीति की निशानी नहीं है

ट्रंप सदा से यूएन को फुंका हुआ कारतूस बताते रहे हैं, अतः ट्रंप द्वारा प्रस्तावित बोर्ड, यूएन में सुधार करने का प्रयास नहीं है, बल्कि उसको खत्म कर एक "ट्रंप यूएन" बनाने की कोशिश है

—सुकुमार साह—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 19 जनवरी। संयुक्त राष्ट्र संघ को ट्रंप द्वारा अप्रासंगिक बताकर खुले आम खारिज करने के बाद, नई दिल्ली अमेरिका-नेतृत्व वाले शांति तंत्र को वैधता देने से हिचक रही है, जो बहुपक्षीय मानदंडों में सुधार करने के बजाय उन्हें दरकिनार करता हुआ प्रतीत होता है।

ग़ाज़ा के लिए प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को शामिल होने के लिए डॉनल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर भारत की सोची-समझी चुप्पी ही इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि इस पहल को "ट्रंप संयुक्त राष्ट्र" क्यों कहा जा रहा है। नई दिल्ली के लिए मुद्दा सिर्फ ग़ाज़ा या युद्धोत्तर पुनर्निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं गहरी बेचैनी एक ऐसे वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रीय शासन ढांचे को लेकर महसूस की जा रही है, जिसे एक

अमेरिकी राष्ट्रपति बहावा दे रहे हैं और जो बार-बार और सार्वजनिक रूप से संयुक्त राष्ट्र को "खत्म हो चुकी शक्ति" बता रहे हैं। जब संयुक्त राष्ट्र के प्रति इस

घोषित संदेश को खुद ट्रंप की अध्यक्षता वाले अमेरिका-नेतृत्व वाले, नेता-केन्द्रित शांति निकाय के साथ तुलनात्मक रूप से देखा जाता है, तो भारतीय नीति-निर्माताओं के लिए यह प्रस्ताव किसी तकनीकी व्यवस्था की बजाय बहुपक्षवाद में सुधार के बजाय उसे हटाने का राजनीतिक बयान बन जाता है। भारतीय दृष्टिकोण से यह बेहद अहम है। भारत लंबे समय से यह कहता आया है कि संयुक्त राष्ट्र वृष्टिपूर्ण, अल्प-प्रतिनिधित्व वाला है और उसमें तत्काल सुधार की जरूरत है, खासकर उसमें ग्लोबल साउथ की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करना जरूरी है। लेकिन भारत यह भी उतनी ही (शेख अंतिम पृष्ठ पर)